भारत को संयम की नसीहत और खुद की हिंसा पर चुप्पी

लक्ज़मबर्ग/नई दिल्ली, 07 जनवरी। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पश्चिमी देशों की कथित दोहरी नीति पर खुलकर सवाल खड़े किए हैं। लक्ज़मबर्ग में भारतीय समुदाय से बातचीत के

विदेश मंत्री एस. जयशंकर का पश्चिम पर तीखा प्रहार

दौरान उन्होंने कहा कि कुछ देश दूर बैठकर भारत-पाकिस्तान तनाव पर चिंता जताते हैं और मुफ्त की सलाह देते हैं, लेकिन अपने इलाकों में हो रही हिंसा, सैन्य हस्तक्षेप और भू-राजनीतिक तनावों को नजरअंदाज कर देते हैं।

जयशंकर का यह बयान वैश्विक राजनीति में चयनात्मक नैतिकता को उजागर करता है।

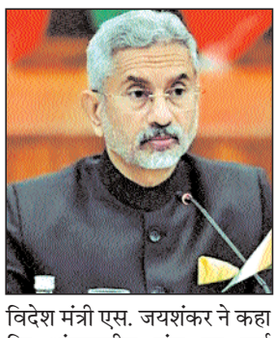

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर कई पश्चिमी देश एक ही मुद्दे पर अलग-अलग पैमाने अपनाते हैं। उन्होंने मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए बताया कि अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की थी। विदेश मंत्री का कहना था कि जब पश्चिमी शक्तियां अपने हितों के लिए नौसैनिक संपत्तियां भेजती हैं, सरकारें गिराने की कोशिश करती हैं या संसाधनों पर नियंत्रण चाहती हैं, तब उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है। लेकिन जब भारत आतंकवाद के खिलाफ सीमित और लक्षित कार्रवाई करता है, तो उसे उपदेश दिए जाते हैं। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत अब इस तरह की दोहरी सोच को स्वीकार नहीं करेगा। भारत अपनी संप्रभुता, नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक भू-राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं।

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वेनेजुएला या आसपास के इलाकों में अमेरिकी बमबारी होती है, तो गांवों में रहने वाले किसान हथियार उठा सकते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध शुरू हो सकता है। पेट्रो के मुताबिक, ऐसी स्थिति पूरे लैटिन अमेरिका को अस्थिर कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी ऐसे राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिसे देश की बड़ी आबादी सम्मान देती है, तो जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ेगा।

ट्रम्प के अनुसार, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल प्रतिबंधित कच्चा तेल सौंपेंगी। यह तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा और इससे मिलने वाली रकम पर अमेरिकी नियंत्रण रहेगा। मौजूदा कीमतों के हिसाब से इस तेल की कीमत करीब 25 हजार करोड़ रुपये आंकी जा रही है। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रूथ सोशल' पर बताया कि उन्होंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को इस योजना को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं।

यूएई के बाद श्रीलंका पहुंचे सेना प्रमुख

रक्षा सहयोग पर की जाएगी चर्चा

नयी दिल्ली 07 जनवरी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका की दो देशों की यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को श्रीलंका पहुंच गये। दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका गये जनरल द्विवेदी श्रीलंका के वरिष्ठ सैन्य और नागरिक नेतृत्व से मुलाकात करेंगे जिनमें

श्रीलंका सेना के कमांडर, उप रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव शामिल हैं। इस दौरान प्रशिक्षण सहयोग, क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। जनरल द्विवेदी डिफेंस सर्विसेज

कमान और स्टाफ कॉलेज में अधिकारियों को संबोधित करेंगे और बुट्टाला स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में अधिकारियों तथा प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे। उनकी यात्रा श्रीलंका के साथ रक्षा शिक्षा और पेशेवर सैन्य आदान-प्रदान के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारतीय सेना की इंजीनियर टास्क फोर्स ने श्रीलंका में हाल ही में आये दितवा चक्रवात के कारण बंद पड़े बी-492 राजमार्ग पर 100 फुट लंबे बेली ब्रिज का निर्माण किया है, जिससे मध्य प्रांत (कैंडी) और उवा प्रांत (बदुल्ला) के बीच महत्वपूर्ण सड़क संपर्क बहाल हुआ। यह पुल श्रीलंका में तूफान के कारण हुई भारी तबाही के बाद ऑपरेशन सागर बंधु के तहत बनाया गया। मानवीय सहायता के तहत भारतीय सेना, श्रीलंका सेना और रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के समन्वय से बाधित संपर्क मार्गों को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग सहायता प्रदान कर रही है।

राजस्व खुफिया एजेंसी ने पकड़ा 40 करोड़ का सोना

नयी दिल्ली, 07 जनवरी (वार्ता) केंद्रीय वित्त मंत्रालय की खुफिया एजेंसी राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने सोने की तस्करी में लगे एक नेटवर्क का भंड़ाफोड़ करते हुए 40 करोड़

दुबई से संचालित गिरोह का भंडाफोड़

रुपये कीमत का 29 किलोग्राम सोना और 2.9 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की है। इस नेटवर्क के तार दुबई और बंगलादेश से जड़े थे और यह माल त्रिपुरा के रास्ते आता था।

वित्त मंत्रालय की बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है दिल्ली और अगरतला में मंगलवार को छापेमारी और तलाशी की कार्रवाई से इस नेटवर्क का पता चला है। इस गिरोह में शामिल अपराधी दुबई और बंगलादेश के रास्ते सधे तरीके से तस्करी का सोना भेजते थे। इस कार्रवाई में पकड़े गये सोने के बिस्कुटों पर विदेश का ठप्पा लगा है। बयान में कहा गया है ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर मंगलवार को इस गिरोह का एक सदस्य त्रिपुरा में अगरतला में तस्करी के माल की एक खेप लेते हुए पकड़ा गया।

भारतीय महिलाओं को मिलेगी त्वरित सहायता

टोरंटो में भारतीय महिलाओं के लिए खुला मदद का नया केंद्र

टोरंटो, 07 जनवरी। कनाडा में रह रही भारतीय महिलाओं के लिए अब मुश्किल हालात में मदद पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। टोरंटो स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास में हाल ही में स्थापित किया गया 'वन स्टॉप सेंटर फॉर विमेन' अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है।

इस केंद्र का उद्देश्य उन भारतीय मूल की महिलाओं को त्वरित और भरोसेमंद सहायता देना है, जो घरेलू हिंसा, शोषण, वित्तीय संकट, कानूनी उलझनों या भावनात्मक दबाव जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। कई बार विदेशी जमीन पर भाषा, संस्कृति और सामाजिक झिझक के चलते महिलाएं खुलकर अपनी परेशानी साझा नहीं कर पातीं। ऐसे में यह केंद्र एक सुरक्षित और संवेदनशील मंच के रूप में सामने आया है, जहां पीड़ित महिलाओं की बात सुनी जाती है और उन्हें सही दिशा में मदद से जोड़ा जाता है। खास बात यह है कि यह सुविधा सिर्फ स्थायी निवासी महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्राएं, वर्क परमिट पर काम कर रही महिलाएं और विज़िटर वीज़ा पर आई महिलाएं भी इसका लाभ ले सकती हैं। टोरंटो में भारत के कार्यवाहक महावाणिज्य दूत कपिध्वज प्रताप सिंह के अनुसार, इस वन स्टॉप सेंटर को बनाने का मुख्य मकसद कनाडा और भारतीय समुदाय के बीच एक मजबूत सेतु तैयार करना है।

उन्होंने बताया कि कनाडा में रह रही कई भारतीय महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद, छोड़ दिए जाने, मानसिक शोषण और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन सांस्कृतिक दबाव और सामाजिक डर के कारण वे मदद लेने से कतराती हैं। यह सेंटर कनाडा के स्थानीय कानूनों के दायरे में काम करते हुए महिलाओं को वहां मौजूद कम्युनिटी रिसोर्स, सोशल सर्विस एजेंसियों और कानूनी संस्थाओं से जोड़ता है।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हो रहे हमलों पर भड़के वाड्रा

नयी दिल्ली 07 जनवरी। उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा ने बंगलादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर वहां की सरकार की कड़ी आलोचना की है। बुधवार को सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में श्री वाड्रा ने हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया।

उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट किया कि किसी भी देश की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासन की नाकामी या वैचारिक बदलाव किसी भी समुदाय पर हिंसा और उत्पीड़न को सही नहीं ठहरा सकते। उन्होंने कहा कि यह

चिंताजनक है कि किसी अन्य देश की आंतरिक अव्यवस्था का खामियाजा भारतीयों और विशेषकर हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। श्री वाड्रा ने जोर देकर कहा कि मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को कभी भी राजनीतिक अराजकता की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता।

आईआईटी (बीएचयू) में 15 से शुरू होगी 'काशीयात्रा 2026'

वाराणसी, 07 जनवरी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में चार दिवसीय सामाजिक-सांस्कृतिक महोत्सव 'काशीयात्रा 2026' का 15 जनवरी को शुभारंभ होगा। साहित्य, संगीत, कला एवं रचनात्मक अभिव्यक्तियों का यह महोत्सव 15, 16, 17 और 18 जनवरी तक चलेगी। यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यह महोत्सव प्राचीन परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण वाराणसी नगरी, आईआईटी (बीएचयू) की शताब्दी-पुरानी शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उत्कृष्टता की परंपरा को और भी सशक्त बनाता है।

पंजाब में 42 हजार तस्कर गिरफ्तार : केजरीवाल

नशे की जड़ पर आम आदमी पार्टी करेगी सीधा प्रहार

नई दिल्ली, 07 जनवरी। पंजाब में नशे के खिलाफ चल रही लड़ाई को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। एक साक्षात्कार में केजरीवाल ने कहा कि राज्य में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान को अभूतपूर्व स्तर तक तेज किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 42 हजार से

अधिक नशा तस्करों को पकड़ा जा चुका है, जो सरकार की सख्त मंशा को दर्शाता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में नशे की समस्या को लेकर सरकार की कार्रवाई को अब तक की सबसे सख्त और निर्णायक लड़ाई बताया है।

एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि पंजाब लंबे समय से नशे की मार झेल रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे सिर्फ मुद्दा नहीं, बल्कि मिशन बनाकर अपनाया है। केजरीवाल ने कहा कि नशा केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह युवाओं के भविष्य और समाज की सेहत से जुड़ा सवाल है। इसी सोच के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार ने नशे के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने दावा किया कि अब तक 42 हजार से ज्यादा स्मगलरों और नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनका कहना था कि यह अभियान सिर्फ पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रशासन, खुफिया एजेंसियों और स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी को भी जोड़ा गया है। नशे की सप्लाई चेन तोड़ने के साथ-साथ नशा मुक्ति और पुनर्वास पर भी काम किया जा रहा है,

बरेली में एएनटीएफ ने तीन अंतर्राज्यीय तस्कर दबोचे

लखनऊ/बरेली 07 जनवरी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) उत्तर प्रदेश की बरेली इकाई ने अवैध मादक पदार्थों के कारोबार करने वाले तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है।

52.5 किलो एसीटिक एनहाइड्राइड और 640 ग्राम स्मैक बरामद

प्राप्त जानकारी के अनुसार एएनटीएफ आरोपियों के कब्जे से 52.500 किलोग्राम एसीटिक एनहाइड्राइड, 640 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन, एक इनोवा कार, तीन मोबाइल फोन और 1,03,520 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। बरामद मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 43 लाख रुपये बताई जा रही है। एएनटीएफ अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई मंगलवार को बरेली जिला में रामपुर राजमार्ग पर रहमतुल्ला मोड़ के पास की गयी। पकड़े गए तस्कर अंतरराज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थे। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान ओमेंद्र, मनोज, शाकिर के तौर पर हुई है। अभियुक्तों ने बताया कि वे स्मैक/हेरोइन बनाने में प्रयोग होने वाले केमिकल एसीटिक एनहाइड्राइड की सप्लाई करते थे।

भारत बना जैव-बिटुमेन उत्पादन में अग्रणी

कृषि अपशिष्ट से सड़क निर्माण तक आयात पर निर्भरता घटाने की बड़ी पहल

नई दिल्ली, 07 जनवरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि भारत जैव-बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।

श्री गडकरी ने बुधवार को यहां वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समारोह %फॉम फार्म रेजड्यू टू रोड- पायरोलिसिस के माध्यम से बायो-बिटुमेन% को संबोधित करते हुए इस उपलब्धि को भारत के सड़क बुनियादी ढांचे के लिए एक ऐतिहासिक मील का

पत्थर बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कृषि अपशिष्ट को एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन में बदला जा सकता है। जैव-बिटुमेन को उन्होंने विकसित भारत 2047 के विज़न की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम करार दिया। सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि कृषि से उत्पन्न अपशिष्ट का उपयोग करने से फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है और चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।

गडकरी ने कहा कि जैव-बिटुमेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सतत विकास, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए अनुसंधान परिषद और उसके वैज्ञानिकों को बधाई दी तथा निरंतर सहयोग के लिए अपने सहयोगी मंत्री जितेंद्र सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। जैव-बिटुमेन एक नवीकरणीय, पेट्रोलियम-मुक्त सामग्री है, जिसमें चिपकने वाले गुण होते हैं और इसका उपयोग सड़कों के निर्माण तथा वॉटरप्रूफिंग में किया जाता है।

एक नजर में

संघर्ष विराम के बाद सैनिकों को यूक्रेन भेजेंगे : मैंक्रो

पेरिस. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम होने के बाद वह यूक्रेन में शांति बरकरार रखने के लिये हजारों फ्रांसिसी सैनिक तैनात कर सकते हैं। उन्होंने यहां मंगलवार को पश्चिमी और यूरोपीय देशों की एक बैठक के दौरान फ्रांस-2 टीवी चैनल के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फ्रांस संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर होने के बाद रूस-यूक्रेन सीमा की देखरेख के लिये अभियानों में हिस्सा लेगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि फ्रांसिसी सैनिक यूक्रेन में युद्ध के लिये नहीं जायेंगे। फ्रांस की भूमिका यूक्रेनी सेना के पुनर्निमाण तक ही सीमित होगी। श्री मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन, यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच बातचीत हुई है और यही देश फैसला करेंगे कि सीमा का उल्लंघन हुआ है या नहीं। उल्लेखनीय है कि 30 पश्चिमी और यूरोपीय देशों ने मंगलवार को यहां एक बैठक में इस बात पर सहमति जताई कि भविष्य का कोई भी शांति समझौता यूक्रेन के लिये मज़बूत और बाध्य सुरक्षा गारंटियों के बिना नहीं होगा।

वस्त्र मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुवाहाटी में आज से

नई दिल्ली. वस्त्र मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुवार को असम के गुवाहाटी में शुरू होगा जिसमें देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वस्त्र मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से आयोजित दो दिन के सम्मेलन की विषय वस्तु भारत का वस्त्र उद्योग-विकास, विरासत और नवाचार का संगम है। सम्मेलन का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में नीति, निवेश, स्थिरता, निर्यात, अवसंरचना विकास और प्रौद्योगिकीय उन्नति पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह सम्मेलन भारत को 2030 तक वैश्विक वस्त्र विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करने के सरकार के विजन के अनुरूप है। इसमें निर्यात को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और समावेशी विकास पर विशेष बल दिया गया है, जो विकास भी, विरासत भी के आदर्शों पर आधारित है। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा, वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन सत्र में भारत की वस्त्र उद्योग की शक्ति, नवोन्मेषण और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी के साथ-साथ पवेलियन का भी उद्घाटन किया जाएगा।

दिल्ली में पत्थरबाजों पर एक्शन शुरू

अतिक्रमण हटाने पर बवाल, पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग

नई दिल्ली, 07 जनवरी. दिल्ली के रामलीला मैदान के पास बुधवार तड़के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान स्थानीय लोगों के पथराव करने से पांच पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गये।

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने राष्ट्रीय राजधानी में रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अवैध ढांचों के खिलाफ हटाने का अभियान शुरू किया था, तभी यह घटना हुई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निधिन वालसन ने मीडिया कर्मियों से कहा कि लगभग 25-30 लोगों ने पुलिस

टीमों पर पत्थर फेंके, जिसमें पांच पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गये। उन्होंने कहा, हमें स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। वहां एक बैंक्वेट हॉल और एक दवाखाना था, जिन्हें गिरा दिया गया है। यह अभियान रात में चलाया गया, ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि पथराव में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आज का इतिहास

1026- सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूट कर उसे नष्ट कर दिया।

1790- अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने पहली बार देश को संबोधित किया।

1884- प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन का जन्म।

1929- भारतीय अभिनेता सईद जाफरी का मालेरकोटला में जन्म।

1929- नीदरलैंड्स और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेलीफोन संपर्क स्थापित।

1942- प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का जन्म।

1952- जॉर्डन ने संविधान अंगीकार किया।

केरल में स्तन कैंसर के सबसे ज्यादा मामले : अध्ययन

तिरुवनंतपुरम, 07 जनवरी। भारत में स्तन कैंसर के आंकड़े भयावह हैं जिनसे पता चलता है कि देश में हर चार मिनट में एक महिला में स्तन कैंसर की पुष्टि हो रही है और केरल में इस बीमारी की व्यापकता देश में सबसे अधिक है।

अध्ययनों से पता चलता है कि केरल में प्रति एक लाख की आबादी पर 35 से 40 स्तन कैंसर के मामले सामने आते हैं। जिलावार आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले तिरुवनंतपुरम जिले में हैं। इसी पृष्ठभूमि में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आठ जनवरी को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में केरल फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी द्वारा आयोजित राज्यव्यापी स्तन कैंसर जागरूकता अभियान मेगा पिंकथॉन के समापन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

बोले चौहान | **बीज, खाद, कीटनाशक की जांच अब होगी फेसलेस-ट्रेसलेस**

बीसी सखियों की आमदनी में होगी बढ़ोत्तरी

नई दिल्ली, 7 जनवरी. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी की उपस्थिति में आज कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दो समझौता ज्ञापन साइन किए गए।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और डाक विभाग के बीच कृषि इनपुट (बीज, उर्वरक और कीटनाशक) के सैंपलों की सुरक्षित, टैंपर-प्रूफ एवं डिजिटल ट्रैकिंग आधारित ढुलाई के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि दूसरे एमओयू के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय, डाक विभाग और डे एनआरएलएम -के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं और आजीविका के अवसरों के विस्तार पर सहमति बनी। कार्यक्रम में कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह तथा डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

चौहान ने कहा कि घटिया बीज, खाद और कीटनाशक किसानों की सबसे बड़ी पीड़ा है और अब सैंपलों की 'फेसलेस और ट्रेसलेस' ढुलाई से छेड़छाड़, देरी और मैनेजमेंट की गुंजाइश लगभग समाप्त हो जाएगी, जिससे प्रयोगशालाओं को समय पर और विश्वसनीय रिपोर्ट मिल सकेगी तथा मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई संभव होगी। 2 करोड़ से अधिक 'लखपति दीदियां' गरीबी उन्मूलन का अभूतपूर्व मॉडल हैं और नए एमओयू के जरिये डाक विभाग के माध्यम से बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं का विस्तार होने से बहनों की आय में 15 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी की उम्मीद बनेंगी।

पेज एक का शेष

विपक्ष तथ्यात्मक बात नहीं करता...

मनरेगा अधिनियम में रोजगार की यह गारंटी मात्र 100 दिन की थी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वीबी जी-राम-जी योजना देश के सभी गांवों की तस्वीर बदल देगी. यह गरीबों, खेतीहर मजदूरों, किसानों सभी के लिए बेहद लाभकारी है. इस योजना से गांवों के विकास को भी मजबूती मिलेगी. मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे प्रदेश के विकास के लिये सर्वदलीय बैठक बुलाने वाले हैं, जिससे कि सभी के अनुभव का लाभ प्रदेश को मिले, विषय विशेषज्ञों को भी बुलाया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पहले किसानों को कृषि से जुड़े कामों के लिए श्रमिक ही नहीं मिलते थे, पर वीबी जी-राम-जी योजना में कृषि के व्यस्ततम समय, विशेषकर बुवाई और कटाई के समय पर्याप्त मात्रा में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है. इस अधिनियम में राज्यों को एक वित्त वर्ष में कुल 60 दिन की अवधि अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है, बीज बुवाई एवं फसल कटाई की व्यस्ततम समयावधि को भी रोजगार उपलब्ध कराने की अवधि में शामिल किया जा सकेगा. प्रावधान के अनुसार इस अवधि में अधिनियम के तहत शामिल अन्य कार्य नहीं किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में पहले 6 प्रतिशत प्रशासनिक अमला तैनात किया गया था. विकसित भारत जी-राम-जी योजना में इस कार्यकारी अमले की तादाद बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है. इससे योजना के क्रियान्वयन में जवाबदेहिता बढ़ेगी, साथ ही सभी गतिविधियों को पूरी पारदर्शिता से अंजाम दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार तय मानकों के आधार पर देश के हर राज्य को एक निश्चित राशि भी देगी. अधिनियम में ग्रामीण आजीविका निर्माण के स्थाई स्रोत विकसित करने पर जोर दिया गया है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इस अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता और विलम्बित मजदूरी देने का प्रावधान भी रखा गया है. इसमें तहत यदि किसी ग्रामीण परिवार को उसके मांग करने के बावजूद तय समय सीमा के भीतर काम नहीं दिया जाता है, तो राज्य सरकार तय की गई दरों एवं शर्तों के अनुसार संबंधित मांगकर्ता परिवार को बेरोजागारी भत्ता देने के लिए भी बाध्य होगी.